NBT नवभारत टाइम्स

www.delhi.nbt.in

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली ।
बुधवार, 2 मार्च 2016

दिल्ली क्यों तरसे

बारिश के पानी से खत्म होगी प्रॉब्लम

हर साल बरसात के दौरान यमुना में 5 से 6 लाख क्यूसेक पानी आता है जो यूं ही बहकर बेकार हो जाता है। अगर इस पानी को स्टोर करने का इंतजाम हो जाए तो कम से कम 3 से 4 महीने तक दिल्ली को पानी के लिए किसी और राज्य का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। यही नहीं, इस पानी से साउथ वेस्ट दिल्ली के ग्राउंड वॉटर लेवल को भी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी :

तालाब, बावड़ी, कुओं और छत पर जमा हो सकता है बारिश का पानी

अब वॉटर कन्जर्वेशन ही ऑप्शन

Veerendra.Kumar@timesgroup.com

नई दिल्ली : अगर बरसात के दिनों में पानी जमा कर लिया जाए तो दिल्ली में पानी की कमी दूर हो सकती है। तालाब, बावड़ी, कुओं और छत पर बारिश के पानी का जमा कर गिरते ग्रांउड वॉटर का लेवल उठाया जा सकता है। हालांकि राजधानी में ज्यादातर एरिया सीमेंटेड होने और वॉटर कन्जर्वेशन पर अवेयरनेस की कमी से बारिश का पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है। सरकारी इमारतों में जो वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगे हैं, उनकी निगरानी न होने से पता नहीं चल पा रहा है कि जमीन के अंदर जाने वाले पानी की क्वॉलिटी कैसी है?

केंद्रीय भूजल बोर्ड और मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में सालाना करीब 611 मिलीमीटर बारिश होती है। इसमें 494 मिलीमीटर बारिश जुलाई से सितंबर के बीच होती है। राजधानी में बेतहाशा पक्की इमारतें बनने के कारण कच्चा क्षेत्र सिमटता जा रहा है। साथ ही इस पानी जमा करने की सही स्कीम न होने से करीब 220 मिलीमीटर बारिश का पानी नालों के जरिए यूं ही बहकर यमुना में चला जाता है। यह लोगों के किसी काम का नहीं रहता।

वॉटर एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ सरकारी इमारतों में बारिश के पानी जमा

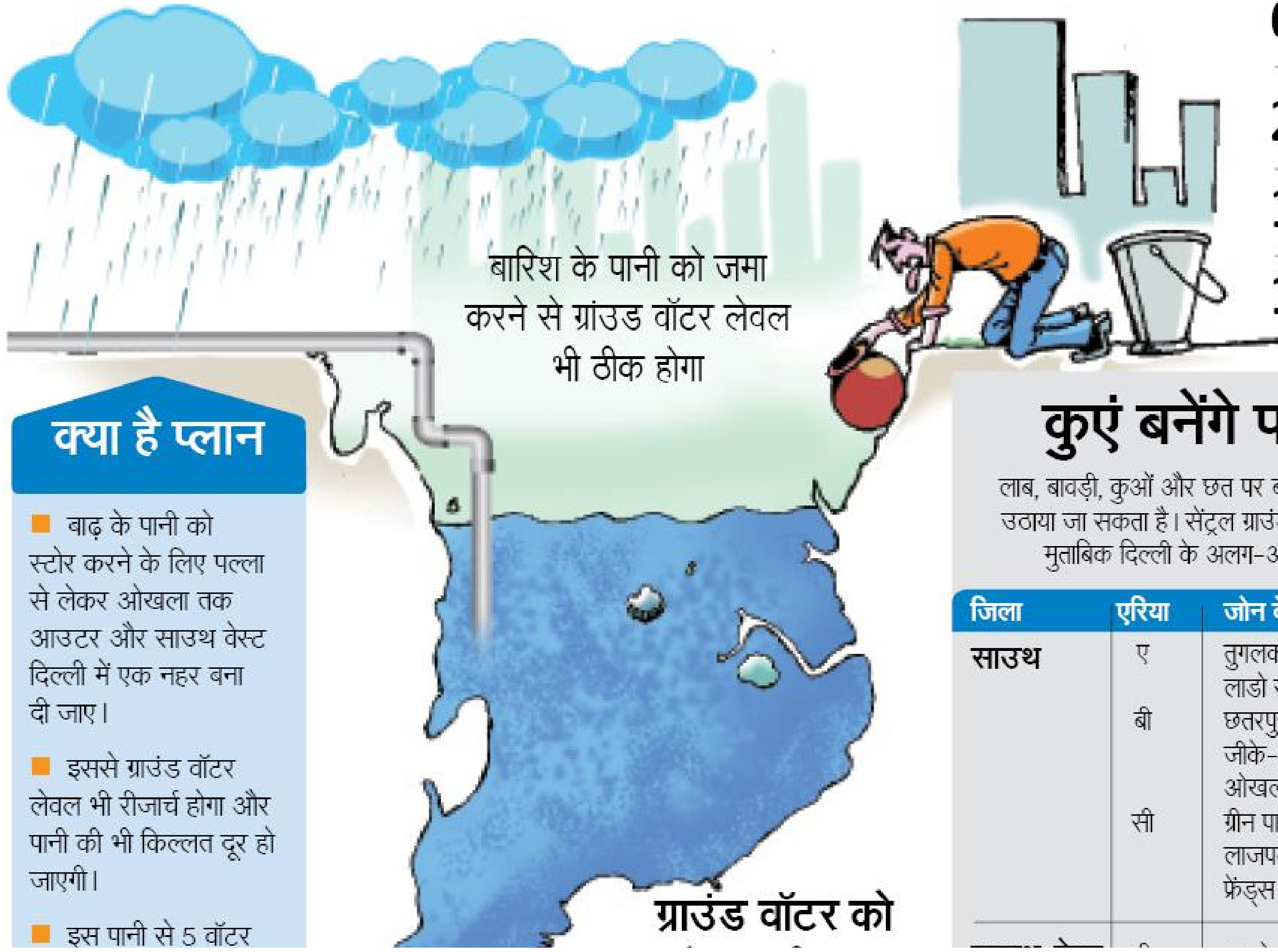

क्या है प्लान

- बाढ़ के पानी को स्टोर करने के लिए पल्ला से लेकर ओखला तक आउटर और साउथ वेस्ट दिल्ली में एक नहर बना दी जाए।
- इससे ग्राउंड वॉटर लेवल भी रीजार्च होगा और पानी की भी किल्लत दूर हो जाएगी।
- इस पानी से 5 वॉटर

611 मिलीमीटर बारिश होती है हर साल दिल्ली में

220 मिलीमीटर पानी बह जाता है बेकार में

140 वर्ग किलोमीटर है राजधानी में छत का एरिया

160 दिन का पानी जमा हो सकता है घर की छत पर

कुएं बनेंगे पानी बचाने का तरीका

लाब, बावड़ी, कुओं और छत पर बारिश के पानी का जमा कर गिरते ग्रांउड वॉटर का लेवल उठाया जा सकता है। सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड के सर्वे के आधार पर की गई सिफारिशों के मुताबिक दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में इस तरह से कुंए बनाए जा सकते हैं

जिला	एरिया	जोन के प्रमुख इलाके	कुओं की गहराई
साउथ	ए	तुगलकाबाद, पुष्प विहार, साकेत लाडो सराय, सैनिक फार्म, मैदानगढ़ी	55-66
	बी	छतरपुर बेसिन और फार्म हाउस जीके-1 और 2, नेहरू प्लेस, सीआर पार्क, ओखला औद्योगिक क्षेत्र	45-35
	सी	ग्रीन पार्क, हौज खास, एनसीईआरटी कैंपस लाजपत नगर, साउथ एक्स, आश्रम चौक, फ्रेंड्स कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, आईआईटी	30-35

'पानी की बर्बादी पर हो एक्शन'

पानी पर आत्मनिर्भर होने का वक्त आ गया है। डैम, नहर और झीलें बनाने के अलावा बारिश के पानी का ज्यादातर यूज होना चाहिए। सरकार को एक्सपर्ट्स से सलाह कर आम जनता की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार संबंधित अफसरों को निर्देश दे कि नियमों का सख्ती से पालन हो। **-लक्ष्मी ममगई**

यमुना पर डैम या बैराज बनाकर दिल्ली को जल संकट से बचाने की आत्मनिर्भर सोच वाकई सराहनीय है। दिल्ली में बारिश के पानी को जमाकर राजधानी को जल संकट के आलावा, बाढ़ जैसी स्थिति से भी बचाया जा सकता है। पानी के जल स्तर को बनाए रखने के लिए अनावश्यक बेसमेंट-खुदाई पर भी रोक लगनी चाहिए, जिससे पानी की बहुत बर्बादी होती है। पानी बर्बादी पर कानून सख्त हो। **-विक्रम ढल्ला**

हर पार्क फेंसिंग घर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। रेजिडेंशल एरिया में बारिश के पानी को संरक्षित रखने के लिए एमसीडी और दूसरी एजेंसियों को नियम बनाना चाहिए। **-राजेश**

पानी को बचा-बचाकर खर्च करना चाहिए। लोगों की आदत है कि पानी मिल रहा है तो उसे बहाते रहें। हाल ही में पानी संकट आया तो सबके होश उड़ गए और पानी की कीमत भी पता चली। पानी उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी जरूरत हो। **-दीप्ति यादव**

यमुना के किनारों को दोनों तरफ से नियंत्रित करके पक्का किया जाए। इस नियंत्रित हिस्से की मिट्टी/ गाद निकालकर इसे उचित गहराई प्रदान कर तली को पक्का किया जाए। इस उपलब्ध स्थान को विभाजित करके एक हिस्सा नाले के लिए बनाकर बाकी स्थान में स्वच्छ पानी संचालित हो। **-महेश जैन**

सेंट्रल रिज मे बनी रंगशाला पानी के ऊपर बनी है और बरसात मे यहां पानी भर जाता है। इस पानी को स्टोर कर के इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह की दूसरी जगह का पता लगाकर बहुत हद तक काम में लाया जा सकता है। **-संजय जोशी**

करने के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तो खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी न तो सही प्रकार से निगरानी हो रही है और न ही रखरखाव का कोई सिस्टम है। जमीन के अंदर किस तरह का पानी जा रहा है, इसकी क्वॉलिटी की भी कोई जांच नहीं हो रही है। यही वजह है कि आज तक किसी भी सरकारी एजेंसी के पास यह डेटा नहीं है कि जमीन के अंदर पानी की कितनी मात्रा जा रही है। अगर जल संचय के दौरान पानी की गुणवत्ता जांच न की जाए तो जमीन के अंदर मौजूद साफ पानी भी दूषित हो जाता है। राजधानी में 80 फीसदी बारिश मॉनसून के दौरान होती है और 20 फीसदी बारिश बाकी मौसम में होती है। इसलिए वॉटर कन्जर्वेशन और जांच प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून दोनों समय में होनी चाहिए।

ट्रीटमेंट प्लांटों को संकट के समय पानी मिल सकता है।

- नहर में जगह-जगह करीब 100 इंजेक्शन वेल बनाए जाएं। इन इंजेक्शन वेल के जरिए पानी जमीन के अंदर छोड़ा जाएगा।
- पूरे साउथ-वेस्ट दिल्ली में ग्राउंड वॉटर लेवल कम है इससे वहां ग्राउंड वॉटर रीचार्ज भी होगा।

बचाने का भी रास्ता

पानी से जुड़े कई विशेषज्ञों का मानना है कि राजधानी में अधिकतर तालाब भर दिए गए हैं। उन पर बड़े-बड़े शॉपिंग सेंटर और फव्वारे बना दिए गए हैं। जो तालाब या जलाशय बचे हैं, उनमें कॉलोनियों का गंदा पानी डाला जा रहा है। इन तालाबों को दोबारा जिंदा करने की कई बार योजनाएं बनी, लेकिन वे फाइलों तक ही सिमट कर रह गईं। अगर छत पर जमा पानी को जमीन के अंदर डाला जाए तो भी गिरते ग्राउंड वॉटर लेवल को उठाया जा सकता है। राजधानी में 140 वर्ग किलोमीटर छत का क्षेत्रफल है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के मुताबिक अगर इस क्षेत्रफल में पानी का संचय किया जाए तो सालाना 76.5 मिलियन क्यूबिक मीटर बारिश के पानी की प्राप्ति हो सकती है। बोर्ड के मुताबिक 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की छत पर 65,000 लीटर बारिश का पानी जमा किया जा सकता है, जिससे 4 सदस्यों वाले परिवार की 160 दिन तक पानी की समस्या दूर हो सकती है।

साउथ-वेस्ट	बी	आरकेपुरम, वसंत विहार, वसंत कुंज, समालखा, महीपालपुर, आईजीआई एयरपोर्ट शंकर विहार, धौला कुआं, नारायणा	45-50
	डी	साउथ-वेस्ट जिला के सेंट्रल और वेस्ट एरिया, नजफगढ़, झड़ौदा कला, द्वारका, पालम	20-25
वेस्ट	डी	उत्तमनगर, जनकपुरी, विकासपुरी, राजा गार्डन, नांगलोई, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, तिलकनगर, मायापुरी, औद्योगिग और वेस्ट जिले के ग्रामीण इलाके	20-25
नॉर्थ-वेस्ट	डी	रोहिणी के भाग, पीतमपुरा, नरेला, सिंघोला, वजीरपुर, उद्योग विहार और औद्योगिक एरिया	20-25
नॉर्थ	डी	आनंद पर्वत, बाड़ा हिंदू राव, घंटाघर एरिया	20-25

(सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड के सर्वे के आधार पर सिफारिश)

भेजें अपनी राय

क्यों होना चाहिए दिल्ली को पानी के मामले में आत्मनिर्भर, कितना फायदा होगा दिल्ली को इस प्रोजेक्ट से, पानी की कमी से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली को और क्या करना चाहिए? आप भी भेजें हमें अपनी राय और सुझाव, हम इन्हें सरकार के सामने रखेंगे।

कैसे भेजें :

nbtdilli@gmail.com

पर मेल करें और सब्जेक्ट में लिखें

Water

ट्विटर पर भी भेज सकते हैं सुझाव

इसके लिए हमारे ट्विटर हैंडल

@NBTDilli

को टैग करें और हैशटैग **#DilliKyunTarse** का इस्तेमाल करें।

ऐसे करें वॉटर कन्जर्वेशन

बेकार पड़े कुओं में

घर के आसपास खाली पड़े कुओं का इस्तेमाल बारिश के पानी का कन्जर्वेशन करने के लिए किया जा सकता है। कन्जर्वेशन से पहले कुओं के तल की सफाई कर लें। बारिश के दौरान छत पर जमा हुए पानी को एक पाइप के जरिए कुएं के तल या उससे नीचे पहुंचाएं। छत का क्षेत्रफल कम से कम 1 हजार वर्गमीटर से अधिक हो तो बेहतर होगा। कुएं के अंदर पानी पहुंचाने से पहले उसे साफ कर लें। बैक्ट्रिया का संक्रमण न फैले इसके लिए नियमित जांच की जानी चाहिए।

हैंड पंप की मदद से

बेकार पड़े हैंडपंप के जरिए भी बारिश के पानी का कन्जर्वेशन किया जा सकता है। एक छोटा घर, जिसकी छत का क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर के आसपास हो, इस तरह के संचय के लिए बेहतर है। छत पर जमा पानी को हैंड पंप तक पहुंचाने के लिए 50-100 मिलीमीटर की पाइप का इस्तेमाल किया जा सकता है।

घर के आसपास गड्ढा खोदकर

जहां पर ग्रांउड वॉटर ज्यादा गहरा नहीं है, वहां 1-2 मीटर चौड़े व 2-3 मीटर गहरे गड्ढे के जरिए बारिश के पानी का संचय किया जा सकता है। करीब 100 वर्ग मीटर की छत पर जमा बारिश के पानी को इस गड्ढे तक पहुंचाया जा सकता है।

तालाबों या झील से

तालाब, सूखी पड़ी झील, यमुना के बाढ़ क्षेत्र में बारिश के पानी का संचय कर राजधानी में गिरते ग्रांउड वॉटर को उठाया जा सकता है।

'We will not harm the Yamuna plains'

COUNTER POINT Art of Living founder say they are using eco-friendly materials, nobody will stay at the venue after 10pm

facetoface

SRI SRI RAVI SHANKAR, Founder, Art of Living

Mallica Joshi
mallica.joshi@hindustantimes.com

NEW DELHI: The 35th anniversary celebrations of the Art of Living course is being held on the Yamuna floodplains amid controversy. The event, expected to attract over 30 lakh people, is scheduled from March 11-13. A petition has been moved against the organisers on the grounds that the event would damage the floodplains. Sri Sri Ravi Shankar, founder of Art of Living, dismissed these allegations in an interaction with HT.

Preparation for the three-day event has not been without controversy, especially with environmentalists moving the National Green Tribunal.

The first thing that we wanted to do was to approach the NGT and take permission. But NGT has no such system. Only when a petition was filed did the NGT have a say at all. We applied for the location as it was well connected and it was willingly allotted.

We would not harm the Yamuna. Nobody associated with the event will stay there. They will come at 5pm and leave by 10pm. The hue and cry that we are destroying the Yamuna floodplain is nonsense.

Is it true that flora has been destroyed?

First of all, there was nothing there but weeds at the location. Secondly, the land is cultivated. If it was virgin land with flora and fauna, I would have been the first one to say 'let's not do anything here, we don't want to destroy anything'. We have not cut any trees. We pruned the branches of four trees because they were obstructing the view.

What of the allegation of dumping debris?

It is incorrect. We have only levelled the land and shifted the mud to the side. How can we use the land if it is not levelled? We only redistributed mud.

> The stage for the event is the largest to be built, equivalent to six football grounds. People from 155 countries are participating in the event.
>
> SRI SRI RAVI SHANKAR, founder, Art of Living

Does your holding this event set a precedent for the use of the floodplain for activities?

If that is the case, the government should not give the opportunity to anyone. They say there will be damage because of high footfall. I don't agree. Festivals have been held for centuries on the banks of the Ganga.

To take the international community to a venue where there is only a gutter is a challenge in itself. This festival will also put pressure on the authorities to at least stop the 17 drains from emptying here. No one protests when sewage is dumped but there are protests when we want to hold a festival.

What is the scale of the event?

The stage for the event is the largest to be built — at 7 acres, equivalent to 6 football grounds. 8,500 musicians will play 50 instruments. People from 155 countries are participating in the event, much higher than participation in Commonwealth Games.

Is there a traffic management plan in place?

We have been in regular touch with the police and 10,000 volunteers are working to make sure the routes are in place.

Any apprehensions about the NGT hearing?

No, we are completely relaxed.

The petitioner alleged that the construction on the floodplains was in violation of the green court's orders. SAUMYA KHANDELWAL/HT PHOTO

NGT adjourns case to Wednesday

NEW DELHI: The National Green Tribunal (NGT) on Tuesday adjourned its hearing on the petition against the Art of Living anniversary celebrations on the Yamuna floodplains to Wednesday.

The NGT bench, headed by chairperson Justice Swatanter Kumar, said it will carry out a day-to-day hearing from Wednesday. The matter, which came up before the tribunal on Tuesday, was postponed on technical grounds. The bench asked the petitioner to clarify if a specific application was made to quash the DDA approval for the event.

On Friday, the on-site report of the NGT appointed expert committee was submitted, according to which there has been large scale devastation of the floodplain. It stated that the Maily se Nirmal Yamuna revitalisation project 2017 was violated and the permission by DDA to the organisers was illegal. **HTC**

THE CONTROVERSY

HT looks at the events leading up to the petition filed in the National Green Tribunal

FACTS ABOUT THE ART OF LIVING EVENT ON THE YAMUNA FLOODPLAINS

1. The three-day Art of Living event is scheduled for March 11-13. Construction of tents, hutments, barricades is underway. Indiscriminate use of rubble in over 1,000 acres of the Yamuna floodplains in East Delhi has been reported.
2. The construction work stand out to the left hand side when one is heading towards Noida or Mayur Vihar from Ashram or Sarai Kale Khan, on the DND Flyway.
3. A plea by activist, Manoj Misra, challenging the event in the NGT stated how "illegal and unauthorised dumping & construction in the active floodplains of the Yamuna is taking place over some 25 hectares upstream of DND flyway."
4. The NGT, in a judgment last year, expressly prohibited all construction activity on the floodplains to preserve the ecology. The tribunal had asked its principal committee to identify structures on the floodplains that needed to be demolished.
5. Members of the Art Of Living foundation said that they have started work "only upon the grant of permission from the authorities/DDA" and are using eco-friendly material like wood, mud, cloth for the construction.

THE IMPORTANCE OF FLOODPLAINS

FLOOD PROTECTION: They give a river more space and decrease pressure on flood protection structures such as dams

WATER QUALITY: Floodplains and flora act as natural filters, removing excess sediment and nutrients, which can degrade water quality.

RECHARGED AQUIFERS: Outside a river's main channel, water flow becomes slow and has more time to seep into the ground. These serve as a primary source of water and are critical for irrigation.

DANGER TO LIFE AND LIMB: Recent floods in Uttarakhand and Chennai were mainly because height of buildings were indiscriminately raised in the floodplains.

PAST TRAGEDY: In 2010, a house collapsed at Lalita Park in East Delhi, killing 71. The building stood on the sandy Yamuna floodplains. Monsoon floods led to seepage in the foundation and in a city, which falls under Seismic zone 4, it was a disaster waiting to happen.

The Tribune
VOICE OF THE PEOPLE

Nation

Centre to verify Haryana govt's Saraswati claim

Published on: Mar 2, 2016, 1:30 AM

Uma Bharti, Union Minister

Ravi S Singh

Tribune News Service

New Delhi, March 1

While the BJP government in Haryana has gone to town claiming discovery of the mythical Saraswati river, the Centre is hedging its bet on it, at least for now.

Union Minister for Water Resources Uma Bharti today said a "task force", headed by Padma Bhushan awardee Dr Kharag Singh Valdiya and comprising water experts and historians, will look into the veracity of the claim.

"The ministry will think further about the river only after its veracity was found," Bharti said.

On whether the Centre will provide help to revive the river, she said it needed to be established whether it was Saraswati. The task force has been asked to ascertain the veracity of the claims of discovery of Saraswati in Haryana and Rajasthan. Traces of underground water flow were found in a Yamunanagar village.

"Yes, underground water of a river has been found. But it has to be established whether the river was indeed Saraswati" - **Uma Bharti, Union Minister**

Illustration: SIDDHANT JUMDE

A 'sweet spot' that cannot mask grim realities

A close reading of the Budget shows that the NDA maintains the squeeze on expenditure, including in social sectors

Prasenjit Bose

Given the widespread agrarian distress, the government has been forced to increase the outlays significantly this year to reverse the damage REUTERS

Budget 2016 has come amidst growing disquiet over the actual state of the Indian economy. Going by the official data, GDP grew at 7.6% in 2015-16 at the back of 7.2% growth registered in 2014-15, making India the fastest growing major economy in the world. Annual inflation, as measured by the wholesale price index (WPI), fell to 0.9% in January 2016. Such a virtuous combination of high growth and falling inflation — if truly reflective of ground realities — is unprecedented in recent economic history. Yet, several other economic indicators do not corroborate such a 'sweet spot'.

The latest Economic Survey itself shows that fixed capital formation has fallen to 29.4% of GDP in 2015-16 from 30.8% in 2014-15. Agriculture has grown by merely 1.1% this year after -0.2% growth last year with food grains production stagnating at around 250 million tonnes for the past two years. Exports and imports have fallen by 17.6 and 15.5%, respectively, during this year. The Railway Budget presented last week reported a mere 1% growth in freight volume in 2015-16 over last year.

Growth in bank credit has ranged between 9 and 11% in the last two years in contrast to an average annual growth rate of over 20% in the last decade. Banks are unwilling to lend owing to a pile-up of bad debts, with stressed advances accounting for over ₹8.5 crore, i.e. almost 7% of GDP. The debt distress afflicting the private corporate sector is acting as a drag on fresh investments. These are certainly not the signs of a booming economy. Moreover, despite crude oil prices (Indian basket) dropping to around $30 per barrel from an average of $84 per barrel last year, annual inflation as measured by the consumer price index has remained over 5%.

The fiscal strategy adopted by the finance minister, however, betrays the sense of complacency pervading the policy establishment. Adherence to a conservative fiscal stance and deficit reduction has been prioritised over everything else. The total expenditure under the UPA-II government (2009-14) averaged around 14.8% of GDP, with plan expenditure averaging 4.5% of GDP and the fiscal deficit at 5.31% of GDP. By 2015-16, the Modi government has squeezed total expenditure in real terms to 13.2% of GDP, with plan expenditure falling to 3.5% and the fiscal deficit to 3.9%. The estimates for 2016-17 provided in Budget 2016 promise to adhere to the same contractionary roadmap, by restricting total expenditure to 13.1%, plan expenditure to 3.6% and the fiscal deficit to 3.5% of GDP.

There has been a shortfall of over ₹45,000 crore in direct tax collections in 2015-16 vis-a-vis the budget estimates made last year. But this shortfall has been more than made up with indirect tax collections overshooting budget estimates by over ₹55,000 crore, mainly on account of the hikes in excise duties on petroleum products. While crude oil prices have come down by over 54% since April 2015, the reduction of the retail price of diesel in Delhi is merely 8%.

Budget 2016 intends to take this regressive trend further, with the finance minister proposing to mobilise additional revenue worth ₹20,670 crore through indirect taxes and cesses, while foregoing ₹1,060 crore in direct taxes owing to the reduction in corporate tax rate and other exemptions. Such reliance on indirect taxes for revenue mobilisation, especially excise duties on petro products, is fraught with risks. While it will soak up demand from the economy, on the one hand, it can also start an inflationary spiral, on the other, if international oil prices start rising again.

Much is being made out of the thrust on agriculture and rural areas in Budget 2016. The fact is that there was a cut in the nominal outlays for agriculture and irrigation in last year's Budget by almost ₹5,500 crore. Given the widespread agrarian distress, the government has been forced to increase the outlays significantly this year to reverse the damage. While the outlay for agriculture and irrigation has increased from 0.19% of GDP in 2015-16 to 0.32% in 2016-17, the outlays for the social sectors (health and education), rural development and energy-infrastructure have remained at the same level in real terms as in the last two years — 1%, 0.7% and 1.5% of GDP, respectively. The allocation for food subsidy has been cut in nominal terms. The much-advertised improvement in the 'quality' of public spending in terms of a spike in capital expenditure has also got reversed in Budget 2016 — after rising from 1.57% of GDP in 2014-15 to 1.75% of GDP in 2015-16, it is estimated to fall to 1.64% in 2016-17.

The fact that this government's expenditure commitments in crucial areas are suspect is borne out by the 2015-16 revised estimates on crucial heads. Last year's Budget had estimated a net transfer of ₹8.42 lakh crore to the states as their share of taxes and central grants and loans. In effect, the net transfer to the states has fallen short by ₹21,443 crore. While the plan spending of the Railways for 2015-16 was estimated at ₹1 lakh crore last year, revised estimates suggest a shortfall of ₹17,800 crore.

Last year's Budget had estimated nominal GDP to grow by 11.5% in 2015-16, while it actually grew by only 8.6%. If the nominal GDP growth of 11% for 2016-17, estimated in this Budget, turns out to be an over-estimate yet again, it will further dent the credibility of the government. Complacency can be quite damaging at a time when the global economy is facing a downturn and capital is flying out of the emerging economies.

Prasenjit Bose is an economist and activist
The views expressed are personal

pressreader

THE HINDU

CITIES » DELHI

Published: March 2, 2016 00:00 IST | Updated: March 2, 2016 05:33 IST NEW DELHI, March 2, 2016

NGT to hold daily hearing on fest from today

- Bindu Shajan Perappadan

Environmental activist Manoj Misra has moved the NGT against the event for violating green laws.Photo: Sushil Kumar Verma

: Maintaining that it will be holding day-to-day hearing from Wednesday, the National Green Tribunal (NGT) on Tuesday adjourned the hearing on a plea against an event being organised on the Yamuna flood plains by the Art of Living foundation, headed by Sri Sri Ravi Shankar, for violating environmental laws.

The matter, which came up before the Tribunal on Tuesday, was postponed for a day on technical grounds.

Environmental activist Manoj Misra has moved the NGT against the event. Speaking about the postponed date he explained that the Tribunal asked them if they had moved an application against the Delhi Development Authority (DDA) allowing the event "which we hadn't".

"The postponement happened on a technical issue. DDA being a party to the earlier judgment of January 13, 2015, which doesn't allow such events to be held at the venue could not have given any permission to the event without prior reference to the NGT order. In any case we are addressing the technical issue about this challenge before the Tribunal on Wednesday," he said.

The Art of Living is organising a world cultural festival between March 11 and 13 that is expected to be attended by 35 lakh people from 155 countries, a statement released by the foundation said.

Meanwhile, facing allegations of damage to environment during preparations for its event on the Yamuna flood plains, the Art of Living maintained that it has followed all guidelines and directions of authorities and the National Green Tribunal.

"The Art of Living (AOL) has a huge regard for the environment. We have never violated nor do we have any intention to violate any laws of the country," a statement by AOL spokesperson said.

The group added that they have followed all the guidelines, recommendations, directions of the honourable court and the authorities extending us the permission to hold the World Culture Festival.

Printable version | Mar 2, 2016 1:14:09 PM | http://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/ngt-to-hold-daily-hearing-on-fest-from-today/article8302212.ece

© The Hindu

सीएम ने सदन में की घोषणा : 2022 तक नर्मदा जल का होगा भरपूर उपयोग

1500 करोड़ में शुद्ध होगी नर्मदा

भोपाल @ पत्रिका

mp.patrika.com

लगातार दूषित हो रही प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा को साफ करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को सदन में कहा कि प्रदेश में नर्मदा के शुद्धिकरण के लिए अभियान चलेगा। इसके लिए उन्होंने 1500 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। शिवराज ने कहा कि मां नर्मदा को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा नर्मदा जल का भरपूर उपयोग करेंगे। 2022 तक मध्यप्रदेश अपने हिस्से की एक-एक बूंद का उपयोग कर लेगा। खेती सहित अन्य जरूरी कार्य के लिए नर्मदा पानी का उपयोग होगा। ड्रिप स्प्रिंकलर से सिंचाई की व्यवस्था होगी।

विधायक निधि में अब मिलेंगे दो करोड़

मुख्यमंत्री ने विधायकों की वर्षों की मांग भी पूरी कर दी। उन्होंने सदन में एलान किया कि विधायक निधि अब दो करोड़ रुपए होगी। सीएम की इस एलान से सत्ता और विपक्षी दल के सदस्यों ने सामूहिक रूप से मेज थपथपाकर स्वागत किया।

अभी 80 लाख रुपए थी निधि : मालूम हो अभी विधायक निधि 80 लाख रुपए है। विधायक पिछले कई वर्षों से इसे बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे।

ये भी ऐलान

- किसानों की आय दोगुना करने के लिए रोडमेप तैयार।
- तीन साल में सभी गाँव पक्की सड़क से जुड़ेंगे।
- 2018 तक विद्युत उत्पादन क्षमता 18 हजार मेगावाट की जाएगी।
- शहरी विकास पर अगले 4 साल में 75 हजार करोड़ खर्च होंगे।

पत्रिका -2-3-16

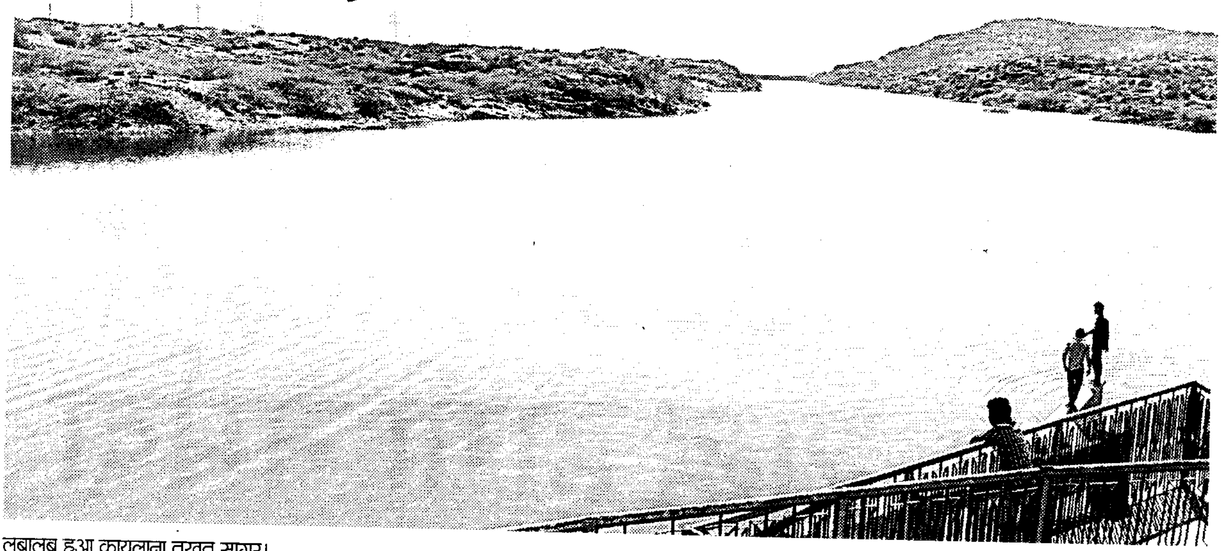
लबालब हुआ कायलाना तखत सागर।

पत्रिका

तैयारी › इंदिरा नहर में अप्रेल से प्रस्तावित है 70 दिन का क्लोजर, जलदाय विभाग ने बढ़ाया जलस्तर, समानान्तर चैनल कैनाल से जलापूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था

क्लोजर के आसार नहीं, पर तैयारी पूरी

जोधपुर में उपलब्ध पानी

54.90 फीट है 58 फीट क्षमता वाले कायलाना का जलस्तर

57.25 फीट पानी है 62 फीट क्षमता वाले तखतसागर में

170 एमसीएफटी पानी है कायलाना में

108 एमसीएफटी पानी है तखतसागर में

278 एमसीएफटी पानी आ चुका जोधपुर के जलाशयों में

जोधपुर @ पत्रिका

rajasthanpatrika.com/city

जलदाय विभाग ने प्रस्तावित क्लोजर को लेकर शहरी जलाशयों का जलस्तर काफी बढ़ा लिया है। इस बीच यह भी सुनने में आ रहा है कि इन्दिरा गांधी नहर के समानान्तर चल रही एक चैनल कैनाल से पानी की आवक की व्यवस्था होने के बाद क्लोजर नहीं होगा। अप्रेल में इन्दिरा गांधी नहर के मेंटेनेंस कार्य को देखते हुए क्लोजर लिया जाना प्रस्तावित है। यह क्लोजर 70 दिन का होना है। क्लोजर अवधि में पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की व्यवस्था के लिए जलदाय विभाग ने पानी का स्टोरेज करना शुरू कर दिया। जोधपुर शहर में पर्याप्त जलापूर्ति के लिए कायलाना और तखतसागर का जलस्तर काफी बढ़ा लिया गया है, ताकि क्लोजर होने की स्थिति में उपभोक्ताओं के लिए पेयजल संकट खड़ा नहीं हो।

दोनों राज्यों ने दी सहमति

सूत्रों ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर की सफाई के दौरान इस नहर के समानान्तर चलने वाली चैनल कैनाल से पानी देने के लिए पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य राजी हो गए हैं। इसके लिए गत दिनों राजस्थान सरकार की ओर से जलदाय विभाग के दो मुख्य अभियंताओं की ओर से इनी राज्यों के उच्चाधिकारियों के साथ इस सम्बन्ध में लम्बी वार्ता हुई। इसमें चैनल कैनाल से पानी देने पर सहमति बनी। इसके बाद जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी ने भी हाल ही जोधपुर में अधिकारियों की बैठक में कहा था कि क्लोजर नहीं होगा, लेकिन पानी के स्टोरज की पूरी तैयारी रखनी है।

हमारी तैयारी जारी

कायलाना और तखतसागर जलाशयों में जलस्तर काफी बढ़ा लिया है। जलदाय मंत्री ने कहा है कि क्लोजर नहीं होगा, लेकिन अभी तक इस बारे में लिखित में निर्देश नहीं मिले हैं। इसलिए पूर्व की तरह हमारी तैयारी जारी है।

दिनेश पडिवाल, कार्यवाहक अधीक्षण अभियंता नगर वृत, जलदाय विभाग

पहले अतिक्रमण हटाओ, फिर साफ करेंगे खान नदी

पत्रिका-2-3-16

केंद्र सरकार की मप्र सरकार को खरी-खरी

मांगी थी 4हजार करोड़ की मदद

स्कंद विवेक धर. नई दिल्ली @ पत्रिका ब्यूरो

patrika.com/india

इंदौर शहर की खान नदी की सफाई को लेकर केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को खरी-खरी सुना दी है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने राज्य सरकार से कह दिया है कि पहले वह खान नदी पर बने अतिक्रमण को हटाए, उसके बाद ही वह नदी को साफ करने में मदद करेगा। मंत्रालय ने फिलहाल किसी भी प्रकार की मदद से इनकार कर दिया है।

केंद्रीय जल संसाधन सचिव शशिशेखर ने पत्रिका को बताया कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के साथ राज्य सरकार और इंदौर नगर निगम के अधिकारियों ने मंत्रालय के साथ एक बैठक की थी। इसके बाद खान नदी की सफाई के लिए राज्य सरकार ने 4 हजार करोड़ की मांग केंद्र से की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।

सचिव ने कहा कि हमने अपनी जांच में यह पाया है कि नदी की हालत बहुत खराब है। इसका सबसे बड़ा कारण नदी पर हुआ अतिक्रमण है। यदि नदी को साफ करना है, तो सबसे पहले अतिक्रमण को हटाना होगा। यह काम जल संसाधन मंत्रालय का तो नहीं है। ये राज्य सरकार को करना है। बकौल जल संसाधन मंत्रालय हम अतिक्रमण हटाने के लिए फंड जारी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमने मप्र सरकार के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। पहले राज्य सरकार खान नदी से अतिक्रमण हटाए, उसके बाद हम इसे साफ करने में राज्य सरकार की मदद करेंगे। इससे पहले खान की सफाई के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती।

गंगा की सफाई से दोगुना मांगे

केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने पिछले 18 महीनों में नमामि गंगे परियोजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं मप्र सरकार ने खान नदी की सफाई के लिए इससे दोगुने 4 हजार करोड़ की मांग कर डाली ।

THE HINDU

Published: March 2, 2016 00:00 IST | Updated: March 2, 2016 08:56 IST March 2, 2016

Uncertainty hangs over mega event on Yamuna floodplains

- Damini Nath

Preparations in full swing on Tuesday for the World Culture Festival, which will be held between March 11 and 13. The stage and the seating for the audience will cover nearly 1,000 acres.Photo: Sushil Kumar Verma

Experts and officials split on environmental affect of the World Culture Festival being organised by the Art of Living Foundation to mark its 35th anniversary

ith just 10 days to go, uncertainty hangs over a giant cultural festival being organised on the floodplains of the Yamuna as experts are divided on whether the event will damage the topography of the area.

The World Culture Festival, being organised by the Art of Living Foundation to celebrate its 35th anniversary, will be held between March 11 and 13 on the floodplains near Mayur Vihar in East Delhi.

Organisers are expecting 3.5 million people to attend over three days, and are building what they call the world's largest stage, which will be spread over seven acres, for artistes to perform. The site stretches over 1,000 acres, flanked by the busy Delhi-Noida Direct Toll Bridge on one side, and the river on the other.

The foundation is aiming for a "mega celebration of diversity". But, there's just one problem. Construction on the floodplains is not allowed, and an environmentalist has moved the National Green Tribunal (NGT) to stop the event from taking place.

While the Tribunal hears the petition filed by Manoj Misra, the convenor of the Yamuna Jiye Abhiyaan, government officials, conservationists and lawyers are divided over the legality of the entire programme.

Vinod Jain, who is called Delhi's "water man" for his efforts to promote conservation, said there was no doubt that such a massive event would damage the floodplains. "They have already altered the topography of the area. The Master Plan-2021 doesn't allow any construction in the floodplains, which have already shrunk from 97 square kilometres to 65 sq. km due to illegal construction," said Mr. Jain.

He added that the floodplains were designated for setting up reservoirs and bio-diversity parks. Delhi could have saved 200 million gallons per day if it had made reservoirs in the floodplains, said Mr. Jain.

The Art of Living, however, denies that the activities are illegal. Akshama Nath, the lawyer representing the foundation in the NGT, said all necessary permissions from relevant departments were attained before work started in mid-December, 2015.

"The allegation against us is that we have caused permanent damage by dumping debris at the site. But, that is not at all the case," said Ms. Nath.

She said the Art of Living had found construction debris spread over 25 acres of the site when it started work.

"We started removing the debris at our own cost after the Delhi Development Authority allowed us to do so," she said.

She denied that any cement or sand had been used to make the massive stands and stage.

"We have kept a safe distance from the riverbed, as ordered by the NGT. The Art of Living has worked to revive dying rivers. It's our mission that the Yamuna lives," said Ms. Nath.

Ministers and officials in the Delhi government have supported the event, with even PM Narendra Modi expected to attend.

An Environment Department official said the event should be allowed to continue as long as the site is returned to its previous condition after the festival.

Delhi Tourism and Culture Minister Kapil Mishra said the event would not damage the river as the construction was temporary. He said he welcomed the festival that would bring visitors from across the world to Delhi.

They (Art Of Living) have already altered the topography of the area (floodplains)

Vinod Jain,conservationist

Over 3.5 million people will attend the three-day event, which will have the world's largest stage — spread over an area of seven acres

---

Printable version | Mar 2, 2016 1:12:43 PM | http://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/uncertainty-hangs-over-mega-event-on-yamuna-floodplains/article8302206.ece

© The Hindu